DAINIK JAGRAN :2 सितम्बर, 2018

1. मुख्य न्यायाधीश ने जस्टिस गोगोई को उत्तराधिकारी बताया

- **वरिष्ठता के सिद्धांत** को ध्यान में रखते हुए जस्टिस रंजन गोगोई को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने की सिफारिश की,
- परंपरा के मुताबिक कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्य न्यायाधीश **अपनी सेवानिवृत्ति से 30 दिन पहले** अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश भेजते हैं,
- असम के रहने वाले जस्टिस गोगोई उस विशेष खंडपीठ का नेतृत्व कर रहे हैं जो पूवरेत्तर राज्यों में नागरिकों की पहचान करने के लिए नेशनल रेजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) को अपडेट करने के मामले को देख रही है।
- **प्रश्न पत्र 2**

2. अमेरिका ने रोकी फलस्तीन शरणार्थी एजेंसी की मदद

- अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र फलस्तीन शरणार्थी एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) की कार्यप्रणाली को दोषपूर्ण बताते हुए इसकी सभी वित्तीय मदद पर रोक लगाने का एलान किया
- एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका एजेंसी को प्रतिवर्ष 36.5 करोड़ डॉलर की सबसे अधिक आर्थिक सहायता देता रहा है|
- **अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध से सम्बंधित**

3. चौबीसों घंटे बिजली के साथ खपत बढ़ाने की भी योजना

- इसके तहत न सिर्फ हर घर में चौबीसों घंटे निर्बाध बिजली देने का काम किया जाएगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि बिजली की गुणवत्ता भी विश्वस्तरीय हो।
- साथ ही बिजली की खपत बढ़ाने के लिए जनता के बीच बिजली से चलने वाले तरह तरह के उपकरणों के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इलेक्टिक स्टोव, इलेक्टिक कारों को बढ़ावा देना सरकार की भावी नीति का अहम हिस्सा होगा।
- नीति आयोग को कहा गया है कि वह खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की खपत बढ़ाने का रोडमैप तैयार करे।
- भारत में हाल के वर्षों में बिजली की खपत तेजी से बढ़ी है, लेकिन दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले प्रति व्यक्ति बिजली खपत यहां अभी भी बेहद कम है। **भारत में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत मार्च, 2018 में 1149 किलोवाट थी, जबकि अमेरिका में यह 12,071 किलोवाट, चीन में 4475 किलोवाट**, यूरोपीय संघ में 5391 किलोवाट थी।
- भारत की स्थापित बिजली की क्षमता 3,45,494 मेगावाट की है जबकि कुल खपत अभी बमुश्किल 1.90 लाख मेगावाट बिजली की है।
- केंद्रीय बिजली मंत्रलय के आंकड़े बताते हैं कि देश के सभी बिजली संयंत्र अपनी क्षमता का महज 56 फीसद ही उत्पादन कर रहे हैं।
- **अनुमान के मुताबिक 14.2 केजी के 8 से 10 सिलेंडरों से एक साल में जितना खाना पकता है, उसके लिए हर दिन चार किलोवाट प्रति घंटा बिजली की जरूरत होगी**। बिजली के मौजूदा दाम के आधार पर इस

©TheCoreIAS

पर इतना ही खर्च आएगा जितना कच्चे तेल का भाव 60 डालर प्रति बैरल होने पर एलपीजी से खाना पकाने पर आता है।

- दूसरे शब्दों में कहें तो अगर कच्चा तेल 60 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर रहे तो बिजली स्टोव पर खाना पकाना देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर होगा।
- देश अपनी जरूरत का 85 फीसद कच्चा तेल आयात करता है जबकि घरेलू स्रोत से पूरी बिजली की आपूर्ति हो सकती है।
- **उर्जा दक्षता में प्रयोग**

4. **गांव के गरीबों के लिए बनेंगे बहुमंजिला आवास**

- जिन इलाकों में जमीन की उपलब्धता कम है वहां पर्यावरण अनुकूल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने का विकल्प तलाशा जाएगा।
- परिसरों में सोलर पैनल से लेकर बारिश का पानी सहेजने तक की सुविधा होगी। इसके लिए आवासीय इमारतें बनाने का काम कर रही सभी संस्थाओं के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि इस संबंध में सेना और रेलवे जैसे विभागों के अनुभव से भी सीखा जा सकता है।
- ग्रामीण विकास मंत्रलय को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए योग्य 3.94 लाख भूमिहीन लाभार्थियों को जमीन उपलब्ध कराने के काम में भी तेजी लाने को भी कहा गया है। ग्रामीण आवास निर्माण में तेजी लाने के लिए मंत्रलय को व्यापक स्तर पर कारीगरों को प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया गया है।
- शहरी आवास और गरीबी उन्मूलन मंत्रलय को खाली पड़े सरकारी आवासों को जरूरतमंद गरीबों को मुहैया कराने का विकल्प तलाशने को भी कहा गया है। साथ ही विभिन्न योजनाओं के तहत बनाई गई और खाली पड़ी इमारतों को भी आवासहीन जरूरतमंद गरीबों को रहने के लिए उपलब्ध कराने की संभावनाएं तलाशने को कहा गया है।
- शहरी आवास और गरीबी उन्मूलन मंत्रलय को नेशनल **अरबन रेंटल पॉलिसी तैयार** करने में भी तेजी लाने को कहा गया है।

5. **बारिश के बाद तालाब में तब्दील हुई राजधानी**

- जलभराव से सबक नहीं ले रहीं एजेंसियां, करोड़ों रुपये नालों की सफाई और मरम्मत पर खर्च, फिर भी कोई असर नहीं
- सड़कों की **गलत डिजाइन** भी हैं जिम्मेदार : अक्सर देखने में आता है कि राजधानी की कई सड़कों पर इसलिए जलभराव होता है, जहां पर सड़क नीचे के स्थान पर बनी है या फिर डिजाइन ही ऐसी है जहां पानी भर सकता है। लेकिन, सड़कों की डिजाइन सुधारने के लिए प्रभावी कदम सिविक एजेंसियों द्वारा नहीं उठाए जा रहे हैं।

शहरीकरण और समस्या

6. **इतिहास में दूसरी बार बैठेंगी सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण महिला खंडपीठ**

- सुप्रीम कोर्ट में अब तक हुई हैं केवल आठ महिला जज

7. **स्थगनादेश की संस्कृति से न्याय में देरी: राष्ट्रपति**

- राष्ट्रपति ने कहा कि मुकदमों में न्याय मिलने में अत्यधिक देरी का **कारण स्थगनादेश की संस्कृति** को मानक बना लेना है।

©TheCoreIAS

- इसका एक कारण **आधारभूत ढांचे में गैप और** रिक्तियां हैं। यह समस्या निचली अदालतों में अधिक है।
- मुकदमों की अधिकता से जज काम के बोझ से दबे हुए हैं। नतीजतन भारतीय कानून प्रणाली को लंबे चलने वाले मुकदमो के लिए जाना जाता है।
- देश की विभिन्न **अदालतों में 3.3 करोड़ मामले लंबित** हैं। इनमें से 2.84 करोड़ लंबित मामले निचली अदालतों में हैं। अन्य 43 लाख लंबित मामले उच्च न्यायालयों में हैं। और करीब 58,000 मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं।
- तकनीकी संसाधनों से न्यायिक डाटा बेस को और सशक्त बनाया जा सकता है।

8 . खेल संस्कृति व भारत

- ऐसी खेल-संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता जहां स्कूलों में छात्रों को खेलो में भाग लेने पर अंक दिए जाये, खिलाड़ियों के लिए नौकरियां सुनिश्चित हों और स्पॉन्सर कठिन समय में उनका साथ देने के लिए तैयार रहे |

सवा करोड़ आबादी वाला हमारा देश अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं की पदक तालिका में कहीं पीछे छूट जाता है। दुख तो तब होता है जब सुविधा और समृद्धि के मामले में हमसे कोसों पीछे देश भी हमारे कान काट देते हैं। राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में तो फिर भी लाज बच जाती है, लेकिन ओलंपिक खेलों में हम फिसड्डी साबित होते हैं। 2012 के लंदन ओलंपिक और 2016 के रियो ओलंपिक में देश को एक भी स्वर्ण पदक नहीं मिला। वहीं 2018 में गोल्डकोस्ट में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत से पीछे रह जाने वाले कनाडा, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका ने 2012 ओलंपिक में क्रमशः दो, छह और चार स्वर्ण पदक जीते थे। 2016 ओलंपिक में भी इन देशों ने स्वर्ण पदक हासिल किए थे। भारत के इन अंतरराष्ट्रीय खेलों में पदकों के मामले में पीछे रह जाने की पांच बड़ी वजहें हैं।

1 फंडिंग की कमी

खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त धन नहीं मिल पाता है। सरकार इस मामले में ढीला ढाला रवैया अपनाती है। लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार के चलते कई बार खेलों और खिलाड़ियों के लिए आने वाली धनराशि उन तक पहुंच ही नहीं पाती है। इस बार एशियाई खेलों में देश का सितारा बुलंद करने वाले कई खिलाड़ियों को निजी कंपनियों से स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ी। कई खिलाड़ी जिनमें देश को स्वर्ण पदक दिलाने की कुव्वत है, वे स्पॉन्सर न मिलने के चलते खेलों को ही अलविदा कह देते हैं। जो खिलाड़ी अपने दम पर पदक जीत लाते हैं, उनपर सरकारें ईनामों की बारिश कर देती हैं। अगर यही धनराशि खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पर खर्च की जाए तो एक की बजाए चार पदक जीते जा सकते हैं।

2 बुनियादी संसाधनों की कमी

कई शीर्ष खिलाड़ी खेलों के प्रति सरकार के उदासीन रवैए के बारे में कह चुके हैं। देश में खेलों के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। विश्वस्तरीय स्पर्धाओं के लिए तैयारी करने वालों को न तो उपयुक्त कोच मिल पाते हैं, न प्रशिक्षण के गुणवत्तापरक उपकरण। हालात सुधर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत... एशियाई खेलों में हेप्टाथलॉन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जी... वाली स्वप्ना बर्मन के दोनों पैरों में छह-छह अंगुलियां हैं। ... में शुरुआती दिनों में उन्हें अपने लिए विशेष जूते नहीं मिले... तो उनका जज्बा था जिसने उन्हें हारने नहीं दिया। ऐसे ही ... के कई खिलाड़ी हैं जो अभावों में प्रशिक्षण ले रहे हैं।

लिहाजा जिन बच्चों में शुरुआत से ही खेलों के प्रति रुझान रहा, उन्हें भी जबरदस्ती कॉपी और पेंसिल थमा दी गई। प्रतिभाएं नैसर्गिक होती हैं। तकनीक और तैयारी से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। खेलों में अच्छा प्रदर्शन देश को वैश्विक फलक पर एक नई बढ़त दिलाता है। ऐसे में सरकारों के साथ समाज को भी अपने मन, कर्म और वचन से देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आगे आना होगा।

- खेलो में अच्छा प्रदर्शन देश को अंतराष्ट्रीय फलक पर एक नई पहचान दिलाता है, ऐसे में सरकारों के साथ साथ समाज को भी अपने मन कर्म और वचन से देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना होगा |

हमें भी यदि खेलों की दुनिया में चीन की तरह सफलता हासिल करनी है तो देश में बुनियादी स्तर से ही खेल संस्कृति का विकास करना होगा। स्कूल से ही बच्चों में खेलों के प्रति रुचि जगानी होगी। बच्चों, और स्कूलों को गेम पीरियड्स का महत्व समझना, समझाना होगा।

3 मौकों की कमी

खेलों के प्रति देश की जनता बहुत उत्साही नहीं है। खिलाड़ियों को अपने परिवार का ही प्रतिरोध झेलना पड़ता है। देश में पढ़ाई को इतनी तवज्जो दी जाती है कि खेल कहीं पीछे छूट जाता है। कई खेलों में खिलाड़ी जैसे-तैसे लड़-झगड़ कर आगे बढ़ते भी हैं, तो उन्हें विश्वस्तरीय प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबला करने के बहुत कम मौके मिलते हैं। ऐसे में वे अनुभव की कमी के चलते ओलंपिक या एशियाई खेलों जैसे आयोजनों में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते।

4 क्रिकेट का क्रेज

देश का आधिकारिक राष्ट्रीय खेल तो कोई नहीं है, लेकिन क्रिकेट को अनौपचारिक तौर पर राष्ट्रीय खेल कहा जा सकता है। देश में क्रिकेट की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। सरकारी फंडिंग और निजी क्षेत्रों की स्पॉन्सरशिप का आधे से ज्यादा हिस्सा अकेले क्रिकेट ही ले जाता है। इस खेल में बरसने वाले अकूत धन को देखते हुए अधिकतर युवा इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। इसके चलते अन्य खेल प्रतिभावान खिलाड़ियों से वंचित रह जाते हैं।

5 मीडिया की कम दिलचस्पी

भारतीय मीडिया भी उन्हीं खेलों को प्राथमिकता देता है, जिन्हें दर्शक देखना चाहते हैं। खेलों के विभिन्न चैनल होने के बाद भी दर्शक न मिलने के कारण कई प्रतिस्पर्धाओं का प्रसारण नहीं किया जाता। ऐसे तमाम खेल हैं जिनके बारे में लोगों को पता तक नहीं है कि उनमें भारतीय खिलाड़ी भी हिस्सा लेते हैं। ऐसे में उन खिलाड़ियों का न तो मनोबल बढ़ता है और न ही उन्हें प्रचार मिलता है। कहीं न कहीं यह उनके प्रदर्शन को प्रभावित करता है।

9 . असहमति की आड़ में अराजकता

- लोकतंत्र में असहमति के लिए स्थान होना ही चाहिए, लेकिन ¨हसक आंदोलनों में लिप्त लोगों को असहमति के अधिकार की आड़ में छिपने का अवसर नहीं दिया जा सकता,

10 . फिर चर्चा में चुनाव खर्च

- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) नामक संस्था का गठन कर वर्ष 1999 में चुनावी खर्च में पारदर्शिता व चुनाव सुधारों से संबंधित काम शुरू किया।
- राजनीतिक दलों की खर्च-सीमा तय करना बेहद जरुरी , लगभग **85** प्रतिशत चंदा कॉर्पोरेट कंपनियों से आता है।
- तकनीक के सहारे जनता को जिम्मेदार बनाने की कोशिश की जा रही है। उदाहरण के लिए चुनाव तारीख घोषित होते ही मध्य प्रदेश चुनाव आयोग एक एप प्रयोग में लाएगा- **सी-विजिल (सिटीजन विजिल)। इसी साल जुलाई में लांच** हुए इस एप को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम चुनाव में प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके माध्यम से चुनाव में हो रही गड़बड़ियों के वीडियो, दस्तावेज और शिकायत भेजे जा सकते हैं। ये सूचनाएं सीधे चुनाव आयोग के सर्वर में जाएंगी।

11. **बैंकिंग सेवाओं से अब तक वंचित रहे सुदूर गांवों में 'डाकिया बैंक लाया'**

- सुदूर गांवों में रहने वाले गरीबों और पिछड़ों को भी डाकियों व डाक सेवकों के मार्फत बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिलने लगा।
- आधार और डिजिटल इंडिया की कड़ी में आइपीपीबी भी जुड़ गया है। सरकार तकनीक के जरिये बदलाव की पक्षधर है और रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म मंत्र के तहत इस तरह के कदम उठाती रहेगी।

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अर्थात आइपीपीबी क्या है ?-

- आइपीपीबी उन गांवों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाएगा जहां सामान्य बैंकों की पहुंच नहीं,
- ग्राहक को **बैंक शाखा जाना अनिवार्य नहीं होगा**। काउंटर के अलावा बैंक डाकियों व डाकसेवकों के मार्फत खुद ग्राहक तक पहुंचेगा।
- **इसके तहत बचत खाता चालू खाता, मनी ट्रांसफर तथा प्रत्यक्ष लाभांतरण के अलावा बिल, यूटिलिटी एवं व्यापारिक भुगतान जैसी अनेक सेवाएं प्राप्त होंगी**।
- यह देश का **सबसे आसान, किफायती तथा भरोसेमंद बैंक** है। अशिक्षित व्यक्ति भी इस प्रणाली का उपयोग कर सकता है। इसमें खाताधारक को अपना खाता अथवा पिन नंबर आदि याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
- ग्राहक को एक **क्यूआर कार्ड** मिलेगा। डाकिए के पास बायोमेटिक मशीन होगी। पैसा जमा करने, भेजने या प्राप्त करने के लिए आधार नंबर के साथ क्यूआर कार्ड को मशीन में डालने के बाद अंगुली रखनी होगी। मोबाइल एप पर भी ये सेवा उपलब्ध होंगी।
- आइपीपीबी **खाते में अधिकतम एक लाख रुपये जमा कराए** जा सकते हैं। इससे अधिक राशि स्वत: डाकघर बचत बैंक खाते में जमा हो जाएगी |
- यह काउंटर सेवाओं के अलावा **माइक्रो एटीएम, मोबाइल बैंकिंग एप, मैसेज तथा इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम (आइवीआरएस) जैसे विविध माध्यमों से सेवाएं** देगा।
- आइपीपीबी को **सीधे कर्ज देने अथवा बीमा पॉलिसी बेचने की अनुमति नहीं** है। लेकिन **थर्ड पार्टी अनुबंधों के जरिये वह ऐसा कर सकेगा**। कर्ज एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए आइपीपीबी ने पंजाब नेशनल बैंक से, जबकि जीवन बीमा के लिए बजाज आलियांज के साथ करार किया है।

12. **अगस्त में जीएसटी संग्रह में घटकर 93,960 करोड़ रुपये**

- जीएसटी संग्रह में गिरावट की एक वजह यह है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में जिन वस्तुओं पर जीएसटी की दर घटायी गयी थी, उनकी बिक्री में विलंब के चलते जीएसटी संग्रह पर असर पड़ा है।

- केरल के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर पांच अक्टूबर 2018 कर दी गयी है। इसका असर भी जीएसटी संग्रह पर पड़ सकता है।

13. **मुनाफे के लिए एनपीए वसूली जरूरी**
    - बीते वित्त वर्ष 2017-18 में देश के 21 सरकारी बैंकों में से सिर्फ दो (विजया बैंक व इंडियन बैंक) को मुनाफा हुआ था। अन्य 19 बैंकों को संयुक्त तौर पर 85,370 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।
    - पिछले वर्ष 2016-17 की बात करें तो 21 में नौ बैंकों को और वर्ष 2015-16 में 13 बैंकों को घाटा हुआ था।
    - **एनसीएलटी में जितनी जल्दी मामलों का निपटारा होगा, उतनी जल्दी हमारे मुनाफे में आने की स्थिति बनेगी। समस्या यह है कि एनसीएलटी में एनपीए के बड़े मामलों को लेकर तेजी से फैसले नहीं हो पा रहे हैं।**
    - आरबीआइ की तरफ से जुलाई, 2017 में एक दर्जन बड़ी कंपनियों के मामले एनसीएलटी में दायर किए गए थे। मकसद था कि इन्हें दिवालिया घोषित करके इनकी संपत्तियों को बेचकर बैंकों के कर्ज वसूले जाएं। अभी तक सिर्फ एस्सार स्टील पर ही फैसला हो सका है जिसे टाटा स्टील ने खरीदा है। अगर चालू वित्त वर्ष के शेष महीनों में एनसीएलटी के तहत अन्य एनपीए को लेकर फैसला हो जाता है तो सरकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधर सकती है।

14. **अमेरिका ने दो पाकिस्तानी फर्मों पर रोक लगाई**
    - परमाणु हथियारों और मिसाइल संबंधी तकनीक के कारोबार से जुड़े होने के शक में पाकिस्तानी कंपनियों पर प्रतिबंध,

15. **चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने चीन-अफ्रीका सम्मलेन-2018 से पहले सेशेल्स के राष्ट्रपति डैनी फाउरे से मुलाकात की।**

16. **आसियान सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे ट्रंप**

17. **लिंक्डइन पर जासूसों की भर्ती कर रहा चीन**
    - चीन की खुफिया एजेंसियां **फर्जी लिंक्डइन अकाउंटों के जरिये अमेरिकी नागरिकों को भर्ती करने** का प्रयास कर रही हैं।
    - अमेरिका ने चीन पर गंभीर आरोप लगाया चीन द्वारा सरकार और कारोबार से जुड़ी गोपनीय जानकारियां पाने की मंशा,

18. **बैरियर रीफ को शिकारी स्टारफिश के नळकसान से बचाएगी रोबोट पनडुब्बी**
    - ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं ने एक ऐसी रोबोट पनडुब्बी का अनावरण किया है, जो ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा करने में मददगार साबित होगी।
    - रेंजरबोट नामक यह रोबोट दुनिया की पहली पानी के नीचे काम करने वाली रोबोटिक प्रणाली है, जिसे खासतौर पर कोरल रीफ वातावरण के लिए डिजाइन किया गया है। यह अपनी रोबोट दृष्टि का प्रयोग कर रीयल टाइम में बाधा से बचने और जटिल विज्ञान मिशन पूरे करने में सक्षम है।
    - यह मल्टी-फंक्शन महासागर ड्रोन कोरल ब्लीचिंग, पानी की गुणवत्ता, कीटों की प्रजातियों की पहचान, प्रदूषण और गंध की जानकारी उपलब्ध कराने में भी मददगार साबित होगा।
    - इसके जरिये कोरल को खाने वाली कांटेदार स्टारफिश की पहचान भी की जा सकेगी और यह उसके खत्म भी करेगा ताकि बैरियर रीफ को नुकसान से बचाया जा सके। बीते कुछ समय में इन स्टारफिश की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है।

©TheCoreIAS

- बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के पूवरेत्तर तट के समांतर बनी हुई दुनिया की यह सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। इसकी लंबाई लगभग 1,200 मील तथा चौड़ाई 10 मील से 90 मील तक है। यह कई स्थानों पर खंडित है। इसका अधिकांश भाग जलमग्न है, लेकिन कहीं-कहीं यह पानी के बाहर भी दिखाई देती है। महाद्वीपीय तट से इसकी दूरी 10 से 150 मील तक है। अध्ययन बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन के बुरे असर से ग्रेट बैरियर रीफ के बचने की संभावना बहुत कम है। ऐसी आशंकाएं हैं कि 2050 तक रीफ पूरी तरह नष्ट हो जाएगी।

19. छत्तीसगढ़ के पुटका पहाड़ में मिला दुर्लभ लाल रंग का फुनगोइड मेढक,

इसकी त्वचा में मौजूद विशेष रसायन से हो सकता है जानलेवा बीमारी का इलाज

- इसकी त्वचा में मौजूद विशेष रसायन स्वाइन फ्लू जैसी जानलेवा बीमारी का इलाज करने में कारगर हो सकता है।1यह मेढक अब तक पश्चिमी घाट में ही देखा गया था। बेहतर खोज के लिए विशेषज्ञों ने पुटका क्षेत्र को संरक्षित घोषित करने की जरूरत बताई है।
- **फुनगोइड कहे जाने वाले इस लाल मेढक के शरीर की ग्रंथियों से अमीनो एसिड से लैस तत्व तब स्त्रवित होता है, जब उसे खतरे का आभास होता है। यह उसे भी बीमारियों से दूर रखने मददगार साबित होता है। यही म्यूकस एच-वन वायरस से लड़ने में कारगर होता है।**
- तिरुवनंतपुरम केरल, पश्चिम घाट अंतर्गत महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में यह लाल मेढक पाया जाता है। पहली बार यह पूर्वी क्षेत्र में देखा गया है।
- ✓ जंगल में पहली बार तेंदुए की तरह दिखने वाला एक दुर्लभ गिरगिट भी दिखा, जिसे वेस्ट इंडियन लेपर्ड (तेंदुआ) गेको कहा जाता है। भारत के वन्य क्षेत्रों में लेपर्ड गेको की मूलत: दो प्रजाति निवास करती हैं। इनमें ईस्ट इंडियन लेपर्ड गेको और वेस्ट इंडियन लेपर्ड गेको शामिल है। लगातार परिवर्तित होते वातावरण व कम होती प्रकृति की वजह से अब यह काफी कम संख्या में रह गए हैं।

20. मंगल पर ऑपरच्यूनिटी रोवर के ऊपर का आसमान हो रहा साफ

- सौर संचालित इस रोवर को सूरज के पर्याप्त रोशनी मिल सकेगी, जिससे यह स्वत: अपनी ठीक स्थिति में लौट सकेगा।

21. नए सेंसर से डॉक्टर रख सकेंगे रोगियों पर नजर

- वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सेंसर विकसित किया है जो खुद की ऊर्जा से संचालित होगा। इससे डॉक्टरों को सर्जरी से उबर रहे दूर-दराज के मरीजों की निगरानी में मदद मिल सकेगी।
- यह ट्यूब जैसी एक छोटी डिवाइस है। इसे सर्जरी के बाद जोड़ों के साथ लगाने के लिए तैयार किया गया। यह डिवाइस बिना किसी तार के सर्जरी के बाद सुधार और रोगी की गतिविधि के बारे में जानकारी कंप्यूटर, स्मार्टफोन या स्मार्टवॉच पर भेज सकती है।
- इस सेंसर को स्वचालित वाहनों के पहियों में लगाने समेत कई दूसरे तरीकों से भी उपयोग किया जा सकता है.

22. डिप्रेशन पीड़ित बच्चों में सामाजिक जुड़ाव का अभाव

- डिप्रेशन (अवसाद) पीड़ित बच्चों को सामाजिक मेलजोल और पढ़ाई संबंधी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
- एक अध्ययन में पाया गया है कि **ऐसे बच्चों में सामाजिक जुड़ाव और शैक्षिक क्षमता** के अभाव का छह गुना ज्यादा खतरा हो सकता है। 6 से 12 साल की उम्र के तीन फीसद बच्चों के डिप्रेशन पीड़ित होने का अनुमान है लेकिन माता-पिता और शिक्षकों के लिए इसकी पहचान आसान नहीं है।

©TheCoreIAS

- माता-पिता और शिक्षकों से बच्चों में डिप्रेशन के स्तर के बारे में जब पूछा जाता है तो वे आमतौर पर पांच से दस फीसद का स्तर ही बताते हैं। उदाहरण के तौर पर शिक्षक यह बताते हैं कि ऐसे बच्चे को क्लास में दोस्त बनाने में दिक्कत होती है।

THE CORE CLASS PROGRAMME

.THE HINDU ANALYSIS EDITORIAL BASED PRE/MAINS DISCUSSION/GUIDANCE CLASS
.ANSWER WRITING 2019 CLASSES
. CSE -2019 PRELIMS/MAINS TEST SERIES

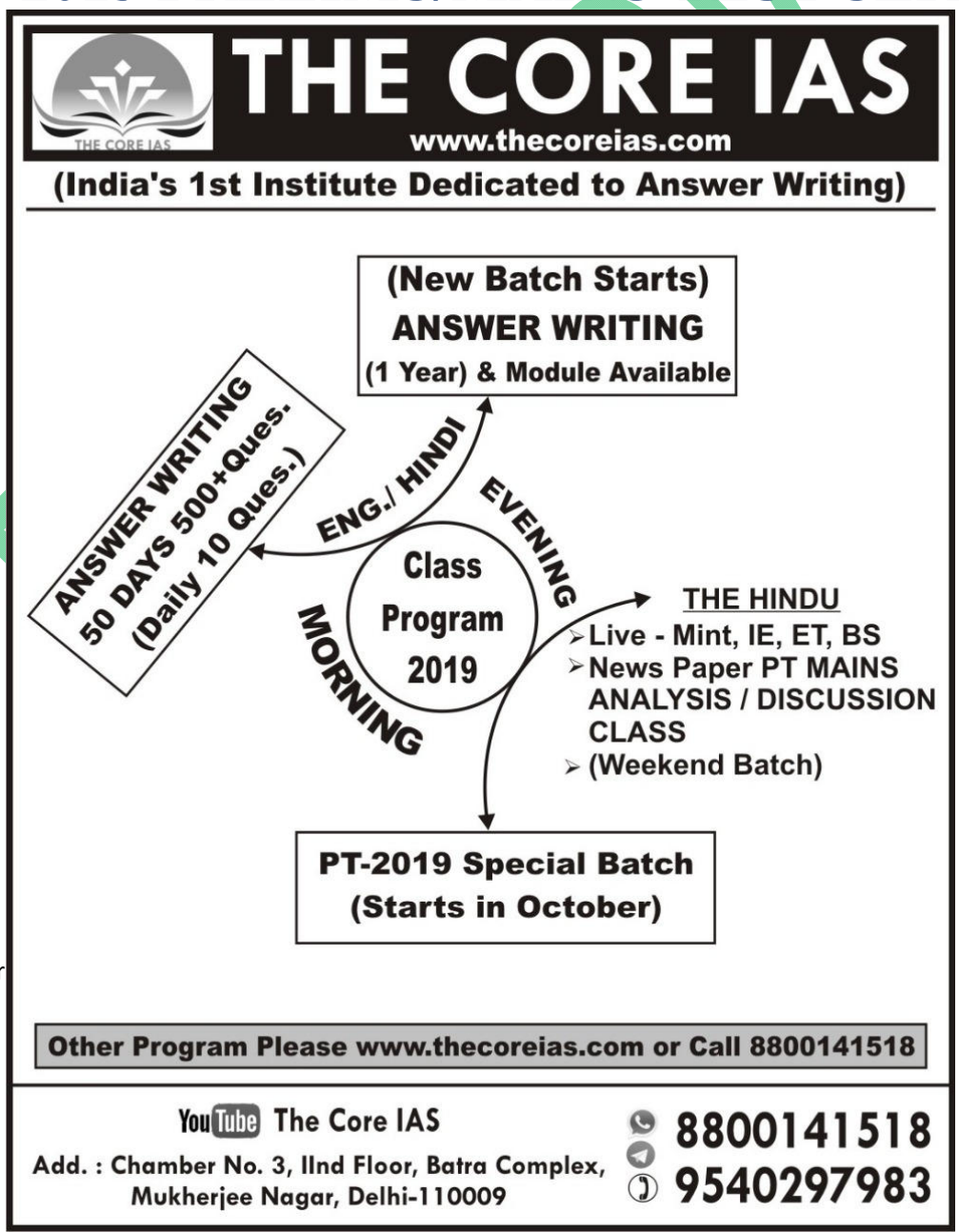

©TheCor